दिनांक 31.07.2017 एवं 01.08.2017 को माननीय मंत्री, कृषि, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

1. ई–किसान भवन :–

1.1 संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला–सह–प्रभारी पदाधिकारी, ई–किसान भवन द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य के सभी 534 प्रखण्डों में ई–किसान भवन बनाने का लक्ष्य के विरूद्ध 409 ई–किसान भवन पूर्ण किया गया है। 47 प्रखण्डों में जमीन अनुपलब्धता के कारण ई–किसान भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसके लिए सरकार के स्तर से संबंधित जिला पदाधिकारी को अविलम्ब जमीन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है।

268 ई–किसान भवन में उपस्कर की सुविधा हेतु स्वीकृति किया जा चुका है। जिसमें से 203 प्रखण्डों में ई–किसान भवन को उपस्कर से सुसज्जित किया जा चुका है।

सहायक निदेशक, सूचना द्वारा बताया गया कि 339 प्रखण्डों के ई–किसान भवन में कम्प्यूटर आपूर्ति कर दी गयी है।

1.2 वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के 11 जिलों यथा बक्सर, नवादा, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगुसराय, कटिहार, समस्तीपुर एवं खगड़िया में जिला स्तरीय तथा 03 प्रमण्डलीय जिलों यथा गया, मुंगेर एवं पूर्णियाँ में प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 6863.36 लाख रूपये से वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पूर्ण किया जाएगा।

1.3 संयुक्त निदेशक (शष्य), दरभंगा का 22179177.00 रू0, संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर का 747983.00 रू0, संयुक्त निदेशक (शष्य), छपरा का 676650.00 रू0 एवं संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा का 6038854.00 रू0 कुल 29642664.00 (दो करोड़ छियानवे लाख बेयालिस हजार छः सौ चौसठ) रूपये की लागत से वर्ष 2016–17 में कार्यालय एवं आवासीय भवनों की मरम्मति (विद्युत पानी एवं शौचालय सहित) हेतु योजना कार्यान्वयन की जा रही है।

2. मिट्टी नमूना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड :– उप निदेशक(रसायन), मिट्टी जॉच प्रयोगशाला द्वारा बताया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत प्रथम चक्र 2015–17 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 13.08 लाख नमूना विश्लेषण के विरूद्ध 10.89 लाख नमूना का विश्लेषण एवं 49.39 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण हुआ है। निदेश दिया गया कि नमूना जाँच कार्य एवं ज्यादा से ज्यादा किसानों को ग्रीड के अनुसार जोड़ कर निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किया जाय। द्वितीय चक्र के वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्य 7.26 लाख के विरूद्ध अबतक मात्र 1.73 लाख नमूना संग्रहण किया गया है। इस लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उप निदेशक, रसायन मिट्टी जॉच प्रयोगशाला)

3. वर्षापात, आच्छादन एवं डीजल अनुदान वितरण :–

3.1 राज्य में 01 जून, 2017 से 30 जुलाई, 2017 तक सामान्य वर्षापात 502.4 मि0मि0 के विरूद्ध 461.00 मि0मि0 वर्षा हुई है। अभी तक धान बिचड़ा का 99 प्रतिशत, धान फसल का 73 प्रतिशत, मक्का का

89 प्रतिशत, दलहन का 57 प्रतिशत तथा तेलहन का 38 प्रतिशत आच्छादन हो चुका है तथा आच्छादन कार्य जारी है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 में डीजल अनुदान हेतु कुल आवंटित राशि 90,43,05,000.00 रू0 के विरूद्ध अभी तक 70,268 आवेदन कृषकों से प्राप्त हुआ है, जिसमें 41,132 आवेदन का सत्यापन किया गया है। अभी तक कोषागार से 87,45000 रू0 की निकासी की गई है जिसमें से 50,41,645.00 रू0 5914 कृषकों के बीच वितरित किया जा चुका है।

4. <u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–</u>

प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा बताया गया कि राज्य के द्वारा राशि खर्च नहीं होने के कारण रा0कृ0वि0यो0 के उद्व्यय में भारत सरकार द्वारा कटौती की जा रही है तथा वर्ष 2014–15 से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेजे जाने के कारण राशि विमुक्ति में कठिनाई हो रही है।

5. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना/राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र :–</u>

5.1 उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र–सह–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित केन्द्र प्रयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना एवं राज्य योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित अद्यतन प्रगति की जानकारी दी गयी। इस क्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना–चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल, जूट एवं गन्ना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा कुल 7629.76 लाख की स्वीकृति दी गयी है जिसके विरूद्ध चावल, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम अंतर्गत कुल 1179.05 लाख रूपये की कार्य उपलब्धि जिलों द्वारा प्रतिवेदित है।

5.2 बताया गया कि 936.64 लाख की लागत से राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना चालु खरीफ मौसम में कार्यान्वित है। इसके अंतर्गत नर्सरी विकास हेतु 5340 एकड़ का लक्ष्य राज्य के सभी 534 प्रखंड़ों में 10 एकड़ प्रति प्रखंड की दर से निर्धारित है। उक्त योजना अंतर्गत नर्सरी विकास करने वाले लाभान्वित कृषक को उपादान क्रय हेतु प्रति एकड़ 7340/– रूपये का अनुदान तथा बिचड़ा क्रय करने वाले किसान को प्रति एकड़ धान रोपनी हेतु बिचड़ा क्रय के विरूद्ध 1000/–रूपये अनुदान का प्रावधान है। 5340 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 3735.50 एकड़ में नर्सरी विकास की उपलब्धि जिलों द्वारा प्रतिवेदित है।

5.3 उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 244 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है जिसमें वर्तमान में 241 कृषि प्रक्षेत्रों में राज्य योजना अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 1987.82 लाख रूपये की लागत से बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। चालू खरीफ मौसम में विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन हेतु 1645 हेक्टेयर में निर्धारित आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध प्रजनक बीज की उपलब्धता के आधार पर 1401.40 हेक्टेयर में आच्छादन की उपलब्धि संभावित है जिसमें धान, अरहर, उड़द, लोबिया, कुलथी, मुंगफली, सोयाबीन, तिल, बाजरा, मरूआ, कौनी, सांवा, जूट एवं मेस्ता के बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

5.4 माननीय कृषि मंत्री, बिहार द्वारा समीक्षा के क्रम में राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन जानकारी ली गयी तथा निदेश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र/संस्थान की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में भेजे गये प्रस्ताव का प्रतिवेदन तैयार करें तथा इस संबंध में प्रस्ताव उपस्थापित करें। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि हस्तांतरण के संबंध में जितने प्रस्ताव आये हैं, उसका भी प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करें।

(अनुमालन–उप निदेशक, शष्य, प्रक्षेत्र)

6. बीज :–

6.1 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा गरमा, 2017 में कार्यान्वित हरी खाद योजना अन्तर्गत ढ़ैचा बीज वितरण तथा खरीफ, 2017 में कार्यान्वित मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकीट धान बीज वितरण योजना, आधार बीज पर अनुदान अंतर्गत बीज वितरण एवं सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि जिलों में उपलब्ध बीज कृषकों के बीच ससमय वितरित किया जा रहा है।

6.2 निदेश दिया गया कि आकस्मिक फसल योजना हेतु बीज की आवश्यकता की मांग जिलों से की जाय तथा जिलों की मांग के अनुसार बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक, शष्य, बीज)

7. उर्वरक :–

7.1 संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र द्वारा बताया गया कि खरीफ में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता जिलों में पर्याप्त मात्रा में है। खरीफ, 2017 हेतु दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक के यूरिया के लक्ष्य 9,50,000 मे0टन0 के विरूद्ध अभी तक 5,15,349 मे0टन यूरिया प्राप्त हो चुका है। डी0ए0पी0 के लक्ष्य 1,75,000 मे0ट0 के विरूद्ध 1,45,283 मे0टन0, एन0पी0के0 के लक्ष्य 100,00 मे0टन0 के विरूद्ध 44,891 मे0टन0 तथा एम0ओ0पी0 के लक्ष्य 60,000 मे0टन के विरूद्ध 66,741 मे0टन0 प्राप्त हो चुका है।

7.2 उर्वरक में डी0बी0टी0 हेतु कुल निबंधित 24,362 खुदरा उर्वरक विक्रेता में से अभी तक 13653 उर्वरक विक्रेता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। अभी तक राज्य में कुल 6501 पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध हुआ है जिसमें से 3579 मशीन विक्रेताओं को वितरित किया जा चुका है। उर्वरक कम्पनियों द्वारा शेष मशीन 12 अगस्त, 2017 तक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

8. पौधा संरक्षण :–

8.1 संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा बतलाया गया कि समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत बीज उपचार कार्यक्रम में बीज टीकाकरण अभियान, फसलों के कीट व्याधि प्रबंधन तथा अन्धाधुन कीटनाशियों के प्रयोग को रोकने की प्रवृति की जानकारी हेतु कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (एफ0एफ0एस0) राज्य के सभी जिले के चार प्रखण्डों में मॉडल के रूप में चलाया जा रहा है। राज्य के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर जैविक कीटनाशी उपलब्ध होगा।

8.2 समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत बीज टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में तीन चक्र अभियान चलाया जायेगा। ऑन दी स्पाट बीजोपचारक रसायन भी

कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध होगा। प्रति चक्र प्रति प्रखण्ड अनुमानित 400 हेक्टेयर क्षेत्र के बीज का टीकाकरण किया जायेगा।

8.3 टाल विकास योजनान्तर्गत टाल क्षेत्र के 6 जिले (पटना, नालन्दा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर एवं भागलपुर) में कृषकों को रासायनिक कीटनाशी के दुष्प्रभाव, कीट–व्याधि का प्राकृति प्रबंधन, जैविक कीटनाशी, फेरोमैनट्रैप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाल क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड में चार–चार कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला चलाया जायेगा ताकि दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

8.4 खर–पतवारनाशी, आवश्यकता आधारित रासायनिक कीटनाशी तथा जैविक कीटनाशी 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध होगा। फेरोमैनट्रैप 90 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध होगा।

8.5 टाल क्षेत्र के अलावे सभी जिले में 50 प्रतिशत अनुदान पर जैविक कीटनाशी उपलब्ध होगा। सभी भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

9. <u>कृषि यांत्रिकीकरण :–</u>

9.1 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा बतलाया गया कि इस वर्ष कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना में कुल 71 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्रस्ताव है। 180.00 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इस वर्ष योजना में ट्रैक्टर को भी शामिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन किसानों को अनुदानित दर पर ट्रैक्टर के क्रय हेतु ट्रैक्टर के साथ जीरोटील सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रील, पैडी ट्रान्सप्लान्टर, रोटावेटर, पैडी थ्रेसर में से कोई दो यंत्र क्रय करना होगा, जिसमें जीरोटील सीड–कम फर्टिलाईजर ड्रील क्रय करना अनिवार्य होगा।

9.2 केन्द्र प्रायोजित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन अन्तर्गत कुल 21.70 करोड़ की कस्टम हायरिंग योजना वर्ष 2016–17 में स्वीकृत प्राप्त हुई है। इसके अन्तर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जानी है। इसके लिए राशि निदेशक, बामेती द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

(अनुपालन–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

10. <u>जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–</u>

10.1 वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग द्वारा बतलाया गया कि वर्ष 2017–18 में 129.77 करोड़ रूपया की योजना कार्यान्वित की जानी है, जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है।

10.2 इस वर्ष निम्न दो जैविक कोरीडोर बनाने का प्रस्ताव है।

- गंगा नदी के किनारे पटना से भागलपुर तक के सभी जिलों में गाँव का चयन कर जैविक खेती की जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दनियाँवा से बिहारशरीफ तक जैविक कोरीडोर बनाने का प्रस्ताव है।

11. <u>दियारा विकास योजना :–</u>

उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़, बिहार, पटना द्वारा बतलाया गया कि कुल 11.76 लाख हे0 दियारा क्षेत्र में से 5.28 लाख हे0 खेती योग्य भूमि है। इस वर्ष दियारा विकास योजना कुल 1420.05 लाख रू0 का स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसके अन्तर्गत हाईब्रिड/उन्नत बीज वितरण,